

राजनीतिक दल और भूमंडलीय लोकतंत्रीकरण:

इतिहास की सीख और भविष्य की संभावनाएं

कैटरीना सेम पाटोमाकी तथा मार्को उल्विला

NIGD Discussion Paper

3/2006

nigd network
institute
for
global
democratization

Discussion Paper 3/2006

ISSN 1458-7823

ISBN-13: 978-952-5455-10-6

ISBN-10: 952-5455-10-6

© लेखकाधीन 2006

अनुवाद: वसुधैव कुटुंबकम टीम, नयी दिल्ली

मुखपृष्ठ को छोड़कर यह किताब 'क्रिएटिव कॉमंस एट्रीब्यूशंस-गैर व्यावसायिक लाइसेंस 2.5 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। इस लाइसेंस की प्रति के लिए कृपया वेबसाइट <http://creativecommons.org/license/by-nc/2.5/> देखें।

इस रचना की प्रतियां बनाने, वितरित व प्रदर्शित करने और इसके आधार पर अन्य कृतियों के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन आवश्यक है – रचना के लेखक का आभार प्रकट किया जाए और इस कृति का उपयोग किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं किया जाए।

एन.आई.जी.डी. – नेटवर्क इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डेमोक्रेटाइजेशन

www.nigd.org

nigd@nigd.org

विषय सूची

भूमिका.....	4
आभार.....	5
1. भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में कुछ विचार.....	6
2. पार्टी इंटरनेशनल – इतिहास और वर्तमान.....	8
3. नए आंदोलन, नयी एजेंसियां.....	10
4. राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत और एजेंसी.....	12
5. तर्कों पर एक गहन-दृष्टि.....	15
6. आगे की बातचीत, शोध और कार्य के विषय में विचार.....	20
उद्धरण.....	24
लेखक-परिचय.....	25

परिशिष्ट

कुछ लेखों के चुनिंदा अंश	26
--------------------------------	----

1. क्षेत्रीय पार्टियां
2. तृतीय इंटरनेशनल- एक भूमंडलीय पार्टी ?
3. राजनैतिक "पार्टी" की बदलती अवधारणा
4. पार्टी इंटरनेशनल तथा वैश्विक सार्वजनिक नीतिगत मुद्दे
5. भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में पांच अवधारणाएं
6. लोकतांत्रिक भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्तें
7. 21वीं सदी में राजनीतिक होने का क्या अर्थ है?
8. अंतर्देशीय लोकतांत्रिक आंदोलनों का उदय
9. नागरिक समाज का गैर राजनीतिकृत पक्ष

भूमिका

बहस के लिए प्रस्तुत यह प्रपत्र एन आई जी डी (नेटवर्क इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डेमोक्रेटाइजेशन) द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट 'भूमंडलीय राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ तत्त्व' के आधार पर तैयार किया गया है। इस प्रपत्र में हमने इस प्रोजेक्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित किया है और भविष्य के कार्यों के लिए अपनी सोच और कुछ शुरुआती विचार प्रस्तुत किया है। इस विषयवस्तु पर हुई महत्वपूर्ण बातचीत की एक झलक दिखलाने के लिए हमने मुख्य सत्रों की बातचीत का सारांश और इसमें भाग लेने वाले लोगों के भाषणों के उद्धरण भी अलग से लिए हैं।

विविध राजनीतिक एवं सामाजिक परिक्षेत्र के अंदर भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के विचार पर बातचीत ही इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रोजेक्ट की कार्यविधि के तौर पर एन आई जी डी द्वारा संचालित एक अन्य प्रोजेक्ट 'भूमंडलीकरण तथा लोकतंत्रीकरण पर उत्तर-दक्षिण संवाद' की कार्यविधि को ही अपनाया गया। इस कार्यविधि के अंतर्गत एन आई जी डी विशेषज्ञों या उनकी टीम को एक निर्धारित विषय-वस्तु पर दी गयी पृष्ठभूमि संबंधी प्रपत्र को आधार बनाकर लेख लिखने का अनुरोध करती है। लेखन की दुनियां से बाहर की बातों को सुनने के लिए बातचीत का भी आयोजन किया जाता है जिसके दौरान राजनीतिक दलों, लोकतंत्र और भूमंडलीकरण से संबंधित बहसों को प्रोत्साहित किया जाता है। सितंबर 2005 और जनवरी 2006 के बीच इन वार्तालापों का आयोजन हेलसिंकी, नयी दिल्ली, बामाको और काराकस में किया गया। जनवरी 2006 के बाद एशिया और यूरोप में विभिन्न स्थानों पर इन मुद्दों पर बहसों का आयोजन किया गया।

इस बातचीत के लिए पृष्ठभूमि संबंधित शुरुआती आलेख और इस प्रक्रिया के लिए तैयार प्रमुख लेखों को एन आई जी डी कार्यकारी प्रपत्र 1/2006 के रूप में 'भूमंडलीय स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीति – भूमंडलीय लोकतंत्रीकरण तथा पार्टियों-व्यवस्था' के नाम से प्रकाशित किया गया। भूमंडलीय राजनीतिक दलों या हमारे वार्तालापों में जिन विविध विषयों पर बातचीत हुई है उनपर गंभीर बहस में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये कार्यकारी प्रपत्र जरूरी पठन सामग्री हैं।

अंग्रेजी भाषा-भाषी क्षेत्र से बाहर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस आलेख का अनुवाद स्पैनिश और हिंदी में किया गया है। भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के विषय से संबंधित सभी दस्तावेज और सामग्रियां www.nigd.org/globalparties वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आभार

हम इस प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान मिलने वाले सहयोग, प्रोत्साहन, रचनात्मक प्रतिक्रियाओं तथा यदाकदा की जाने वाली तीखी आलोचनाओं के लिए लोगों के शुक्रगुजार हैं। इस आलेख को लिखने के दौरान विचारात्मक तथा बहस संबंधी योगदान के लिए हम विशेष रूप से राकेश भट्ट, माइकल बूक, घनश्याम, हर्षमंदर, रॉली मिकेलसन, मिलेट मोरान्टे, जायना पासानेन, विजय प्रताप, पियरे रूसेट, वी.बी. सिंह, ओली टामीलेटो, ताइवो ताइवेनन तथा थॉमस वॉलग्रेन की मूल्यवान प्रतिक्रियाओं के आभारी हैं। हाइकी पाटोमाकी का भी हम विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने इस आलेख के लिए विचारपूर्ण योगदान किया और जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान लगातार रचनात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। स्वाभाविक है कि आलेखों के प्रति आखिरी जिम्मेवारी हमारी ही है।

हम रूबी वैन डर वेक्केन के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने बहस के लिए प्रस्तुत इस आलेख के हिंदी और स्पैनिश अनुवादों के प्रकाशन का संयोजन किया और हेलसिंकी में सितंबर 2006 में आयोजित फीडबैक सेमिनार की व्यवस्था का भार भी अपने ऊपर लिया। इन कार्यकारी आलेखों के बारे में प्राप्त होने वाली अनेक महत्वपूर्ण टिप्पणियों तथा सुझावों के कारण यह सेमिनार महत्वपूर्ण साबित हुआ। बहस के लिए प्रस्तुत इस आलेख पर विचार विमर्श की दृष्टि से इन बातचीतों का आयोजन महत्वपूर्ण रहा है।

रोबिन मिलबर्न आपके द्वारा तत्काल दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं और प्रूफरीडिंग संबंधी मदद के लिए हम आभारी हैं। जॉर्डी लोपेज, जुलियन मोलिना गुइलेन एन एन तथा एन एन— हम हिंदी तथा स्पैनिश अनुवादों के लिए आपके आभारी हैं। फोर्ड फाउंडेशन की ओर से हमारे प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए लीसा जॉर्डन आपका धन्यवाद।

अक्टूबर 2006, हेलसिंकी तथा टैम्पीर, फिनलैंड

कैटरीना सेम पाटोमाकी तथा मार्को उल्विला

“हमारी सहमति के अलावा हर चीज का भूमंडलीकरण हो चुका है। लोकतंत्र स्वयं राष्ट्रराज्य में सीमित हो चुका है। यह राष्ट्र की सीमाओं पर हाथ में सूटकेस लिए बिना पासपोर्ट के खड़ा है।” जॉर्ज मॉनबिऑट 2003 :।

1. भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में कुछ विचार

भूमंडलीकरण के द्वारा पेश की गयी चुनौतियों तथा भूमंडलीय-शासन के नए दौर से राजनीतिक दल किस प्रकार निबट रहे हैं ? क्या भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों की जरूरत है या फिर इसके कारण लोकतंत्र की स्थिति और भी खराब हो जाएगी ?

जब हमने एन आई जी डी के अपने साथियों के साथ इन सवालों तथा भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के विषय में बातचीत शुरू की तो प्रारंभ से ही विचारों की भिन्नता स्पष्ट थी। भूमंडलीय मामलों तथा आंदोलनों के बारे में राजनीतिक सरोकारों के अभाव से निबटने के लिए एक भूमंडलीय राजनीतिक पार्टी के गठन के प्रस्ताव पर परस्पर विरोधी विचार पाए गए। कुछ लोग इस विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे तो कुछ इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि भूमंडलीय शासन के मुद्दे पर राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक साधन की जरूरत है।

जैसे-जैसे यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और आलेख एवं बातचीत के बारे में प्रतिक्रियाएं मिलती गयी, इसी प्रकार की विरोधाभासी प्रवृत्तियां उभर आईं। एक तरफ तो इस बात के बारे में प्रायः सहमति थी कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रकृति में इस अर्थ में बदलाव आया है कि आज अधिकाधिक निर्णय उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं जो लोकतांत्रिक सहभागिता और जनता के नियंत्रण के बाहर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, राजनीतिक दलों के माहौल और दायित्व में अंतर आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी यूरोप में वामपंथी लोकतांत्रिक प्रगति में भी तेजी से ह्रास हुआ है।

हताशा और संकट के इस दौर में लोगों ने नए सिरे से राजनीति में रुचि लेना तथा अपने जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं तथा निर्णयों में भाग लेने की इच्छा जाहिर करनी शुरू की है। यह प्रक्रिया सर्वाधिक स्पष्ट रूप से हाशिए पर धकेल दिए गए बहुसंख्यक समूहों जैसे महिलाओं, युवकों तथा ग्रामीण एवं अनौपचारिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच स्पष्ट दिखाई देती है। भारत में दलित (पहले अछूत कहलाने वाली जाति), ब्राज़ील के मजदूर तथा बोलीविया की आदिम जनजातियों ने ऐसे आंदोलन और पार्टियां खड़ी की हैं जिनका राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन अनुभवों में भी कई प्रकार की समस्याएं रही हैं और इनकी परिवर्तनकारी संभावनाओं का प्रतिफलन देखना अभी बाकी है लेकिन इसकी ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है।

ये दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां एन आई जी डी के प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु रहे हैं। लोकतांत्रिक स्वप्न का साझा

भाव रखने वाले लोगों, संस्थाओं, आंदोलनों तथा पार्टियों के लिए ये प्रवृत्तियां एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। इतिहास की प्रवृत्तियों को समझने के अलावा दुनियां के उपेक्षित बहुसंख्यक लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार के भविष्य की कल्पना भी उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

दुनियां भर में आज हम उसी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो 19वीं सदी के अंत में यूरोप में या 20वीं सदी के शुरुआत में उपनिवेशवाद के शिकार एशियाई देशों में व्याप्त थी। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की थी कि उपेक्षित बहुसंख्यक वर्ग के पास राज्य या बाजार के काम-काज को प्रभावित करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। एक छोटा सा कुलीन-वर्ग अपने तात्कालिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण और उनको लागू करने में सफल हुआ जबकि अधिकतर लोग इसके दुष्परिणामों को झेलने के लिए मजबूर थे। इसलिए हमारी पहल को राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ में परिवर्तनकारी होना आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना नहीं थी, उन्हें इस तंत्र को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

भूमंडलीकरण के इस युग में, राजनीतिक पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क दिखाई नहीं देता। क्या भूमंडलीय राजनीतिक दलों की स्थापना ही इसका समाधान है ?

राजनीतिक पार्टियां इस बात को गलत साबित करती हैं कि भूमंडलीकरण हर चीज को प्रभावित कर रही है। शायद ही कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में भूमंडलीकरण की बात करता है। काफी हद तक राजनीतिक पार्टियां राष्ट्र की हद तक सीमित रही हैं। यह बात यूरोप में पूरी तरह लागू नहीं होती। यूरोपीय संघ ने बहुदेशीय पार्टी-गठनों की शुरुआत की है हालांकि यह भी क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित है। 2003 में यूरोपीय संघ ने यूरोप के स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय सहायता संबंधी नियम और उनसे संबंधित शासकीय नियम बनाए। 2006 तक यूरोपीय संघ की संस्थाओं से वित्तीय सहायता के हकदार 10 यूरोपीय राजनीतिक दलों का निर्माण हो चुका था जो अखिल-यूरोपीय पार्टी गठबंधनों पर आधारित थे। लेकिन यह प्रक्रिया किस हद तक स्वतः स्फूर्त है ? क्या इन अखिल यूरोपीय पार्टियों का उदय यूरोपीय संघ की इस नीति का परिणाम है जिसके अनुसार केवल अखिल यूरोपीय पार्टियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है? इन गठबंधनों का जनाधार कहां है ? क्या ये पार्टियां नीचे से ऊपर की ओर स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय से अखिल यूरोपीय स्तर तक पहुंची है ? अब तक तो ऐसा ही लगता है कि अधिक से अधिक इस प्रक्रिया ने कुछ यूरोपीय तथा भूमंडलीय मुद्दों को जनता की नजर में लाया है।

आर्थिक भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक राजनीतिक स्थान में कमी आयी है। राज्य निवेशकों के लिए सहयोगी व्यापारिक परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राजनीतिक कुलीन वर्ग की सोच कुछ ऐसी हो गई है जिसके अनुसार कॉर्पोरेट भूमंडलीकरण के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन लोग कुछ और चाहते हैं। उदाहरण के लिए 2005 में गैलप-इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 65 प्रतिशत लोगों को लगता है

कि उनका देश जनता की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। पिछले साल यह आंकड़ा थोड़ा कम था।¹ 'पिछले दशक में दुनियां भर के पैमाने पर होने वाले विशाल प्रदर्शनों से भी यह संकेत मिलता है कि वर्तमान प्रवृत्तियां बड़ी संख्या में या अधिकांश विश्व-नागरिकों को स्वीकार्य नहीं है।

पिछले दशकों में, दुनियां भर के पैमाने पर एजेंडा का निर्धारण या निर्णय या तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों द्वारा किया जा रहा है या भूमंडलीय शासन की औपचारिक संस्थाओं द्वारा। भविष्य में आने वाली सरकारें भी भूमंडलीय विनियमों से बंधी होती हैं इसलिए इन परिस्थितियों में जनसामान्य के नैतिक-राजनीतिक विकल्पों की संकल्पना, प्रतिनिधित्व, संप्रेषण और अभिव्यक्ति के लिए ठोस आवश्यकता मौजूद है। लोकतांत्रिक राज्यों में यह कार्य मूल रूप से राजनीतिक पार्टियां करती हैं, फिर भी भूमंडलीकरण के लोकतंत्रीकरण में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में भूमंडलीकरण के विरोधियों द्वारा भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम चर्चा की गई है। राजनीतिक पार्टियों के बारे में लिखे गए अनेक आलेखों में हमें इस बात की याद दिलायी गयी है कि पश्चिमी दुनियां के राजनीतिक दलों में घटती सदस्यता, मतदाताओं की घटती संख्या और नयी पीढ़ी के अभाव जैसी गंभीर समस्याएं देखी जा रही हैं। मतदान का प्रतिशत तो लगातार गिरता जा रहा है। आज वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह की पार्टियां समस्याओं का सामना कर रही हैं। यह घटना इस माहौल में अंदर घटित हो रही है जहां पाश्चात्य राजनीतितंत्र उन पार्टियों के नियंत्रण में है जो 1750 से 1920 के बीच उच्च-आधुनिकता वाले सामाजिक आंदोलनों के दौरान पैदा हुई थीं।

2. पार्टी इंटरनेशनल – इतिहास और वर्तमान

अन्य भूमंडलीय गतिविधियों की तरह, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी संगठन भी 19वीं सदी के आखिरी दौर में पैदा हुए। उदारवादी शांति आंदोलनों से संबंधित वैश्विक गतिविधियों के ठीक पहले 19वीं सदी के मध्य में समाजवादियों, कम्युनिस्टों तथा अराजकतावादियों ने अपनी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करनी शुरू की।

प्रथम इंटरनेशनल (1864–1878) की जड़ें इसकी शुरुआत से कम से कम 20 साल पहले घटित 1848 की क्रांतियों में थीं जो सिसिली में पैदा हुए क्रांतिधर्मी राजनीतिक गतिविधियों से शुरू हुईं और जल्दी ही पूरे यूरोप में फैल गयीं। 1848 की क्रांतियों के अलावा, *प्रथम इंटरनेशनल* की जड़ें 1850 के दशक में फिर से शुरू हुए मजदूर आंदोलनों तथा 1857 के आर्थिक संकट के अंदर ढूँढी जा सकती हैं। इसके अलावा 1859 ई. का इटली का स्वतंत्रता संग्राम, 1861–65 का अमरीकी गृह-युद्ध तथा फ्रांस एवं इंग्लैंड में मजदूरों के आंदोलन ने भी *प्रथम इंटरनेशनल* की पृष्ठभूमि तैयार की। *प्रथम इंटरनेशनल* के इस समाजवादी संगठन ने विभिन्न वामपंथी राजनीतिक समूहों तथा ट्रेड-यूनियन संगठनों को इकट्ठा करने की कोशिश की। जिनेवा में 1866 में आयोजित *प्रथम*

¹ गैलप इंटरनेशनल (2005), वॉयस ऑफ दि पीपुल 2005, ट्रेंड्स इन डेमोक्रेसी, ग्लोबल समरी। यह ऑन लाइन भी उपलब्ध है

इंटरनेशनल में आठ घंटे के श्रमिक दिवस को संघ की एक मौलिक मांग के रूप में स्वीकार किया गया। यह एक महत्वपूर्ण फैसला था। सन 1871 के वसंत में पेरिस पर दो महीने की छोटी सी अवधि के लिए शासन का बागडोर संभालने वाली *पेरिस कम्यून* की पराजय के बाद *प्रथम इंटरनेशनल* के अंदर विघटनकारी प्रवृत्तियां शक्तिशाली हो गयीं। इन विभाजनों के कारण यह संघ धीरे-धीरे कमजोर होता गया और अंततः 1878 में यह पूर्णतः विघटित हो गया।

दूसरा इंटरनेशनल (1889–1916) – *द्वितीय इंटरनेशनल* ने विघटित *प्रथम इंटरनेशनल* के कार्य को आगे बढ़ाया। इसकी स्थापना पेरिस में हुए एक कांग्रेस में की गई और इसमें केवल उन्हीं पार्टियों को शामिल किया गया जो मार्क्सवादी सिद्धांतों को मानते थे। इसका राजनीतिक ढांचा 1880 के श्रमिक आंदोलन के नए उभाड़ और मजदूर वर्ग की पार्टियों खासकर जर्मनी के *सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी* के उदय पर आधारित था। *द्वितीय इंटरनेशनल* के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (1889) के रूप में घोषित करना तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (1910) के रूप में घोषित करना शामिल था।

तीसरा इंटरनेशनल (1919–43)– यह इंटरनेशनल प्रथम विश्वयुद्ध के खिलाफ एकीकृत मोर्चा बनाने में *द्वितीय इंटरनेशनल* की विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ। *तृतीय इंटरनेशनल* के संस्थापक इसे 'बुर्जुआ साम्राज्यवादी युद्ध' मानते थे और संपूर्ण सैन्यविरोधी समाजवादी आंदोलन युद्ध शुरू होने तक पूरी तरह इसके खिलाफ था। *तृतीय इंटरनेशनल* मॉस्को द्वारा अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला औजार भर बन कर रह गया। मित्र राष्ट्रों की आपसी खींचतान के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक यह संगठन समाप्त हो गया।

चौथा इंटरनेशनल (1938–) – इसका जन्म कम्युनिष्ट पार्टियों के अंदर की बहसों एवं विभाजन से संबंधित है। *चौथे इंटरनेशनल* की स्थापना सितंबर 1938 में फ्रांस में सोवियत संघ से निष्कासित ट्रॉट्स्की तथा उसके समर्थकों द्वारा की गई थी। इसके अंदर अनेक विभाजन हुए और अनेक समूह अपने आप को '*चौथा इंटरनेशनल*' कहते हैं। आज भी ऐसे कई समूह हैं जो अपने को *चौथे इंटरनेशनल* तथा इसकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं।

वर्तमान में स्थापित किए गए राजनीतिक पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय संघों में से 1947 में स्थापित '**लिबरल इंटरनेशनल**' सबसे पुराना है। 64 राष्ट्रीय पार्टियों का यह नेटवर्क उदारवाद को प्रोत्साहित करने, उदारवादी दलों को मजबूत करने तथा उदारवादी लोकतंत्र को दुनियां भर में बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। इसका उद्देश्य उन उदारवादी सिद्धांतों के लिए जनसामान्य की सहमति प्राप्त करना है जो इसकी दृष्टि में दुनियां भर के लिए अंतर्राष्ट्रीय है। इसके साथ ही यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दायित्व तथा सामाजिक न्याय पर आधारित एक मुक्त समाज के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है। '*लिबरल इंटरनेशनल*' सदस्य संगठनों के बीच आपसी सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान का एक साधन है। ब्रिटेन के जॉन ऑल्डरडाइस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका सचिवालय लंदन में है।

‘सोशलिस्ट इंटरनेशनल’ – यह *सोशल डेमोक्रेटिक*, समाजवादी तथा श्रमिक पार्टियों का विश्वव्यापी संगठन है। वर्तमान काल में सभी महादेशों के करीब 161 राजनीतिक दल और संगठन इसके सदस्य हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना 1951 में हुई जब इसे फ्रैंकफर्ट कांग्रेस के दौरान पुनः स्थापित किया गया। इसकी जड़ें पहले से मौजूद मजदूर आंदोलनों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच मौजूद थी। इसके बाद इसकी सदस्यता तेजी से बढ़ी है, खासकर हाल के वर्षों में। 1990 के बाद इसकी सदस्यता दुगुनी हो चुकी है। इस इंटरनेशनल के अनेक सदस्य संगठन आज सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। ग्रीस के राष्ट्रपति जॉर्ज ए पापिंद्रु *सोशलिस्ट इंटरनेशनल* के अध्यक्ष हैं और इसका सचिवालय लंदन में है।

इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन 80 से ज्यादा *कंजर्वेटिव*, *क्रिश्चियन डेमोक्रेट* तथा इसी प्रकार की सोच वाली दक्षिणपंथी एवं मध्यमार्गी पार्टियों का संघ है। इनमें 60 से भी अधिक देशों की 80 पार्टियां सदस्य हैं। 1983 में बनाए गए इस संगठन *आई डी यू* में समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ मिलकर नीतिगत तथा संगठनात्मक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करती हैं तथा एक दूसरे से सीखकर साथ कार्रवाई करती हैं, संपर्क स्थापित करती हैं तथा दुनियां भर में मध्यमार्गी – दक्षिणपंथी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वर में बात करती हैं। *आई डी यू* के संस्थापक सदस्यों में मार्गरेट थैचर, जॉर्जबुश (वरिष्ठ), तथा हेलमुट कोल शामिल हैं। *आई डी यू* का मुख्यालय ओस्लो में है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन होवार्ड *आई डी यू* के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

ग्लोबल ग्रीन दुनियां भर की ग्रीन-पार्टियों तथा आंदोलनों का नेटवर्क है जिसकी स्थापना 2001 में हुई है। *ग्लोबल ग्रीन* दुनियां भर की ग्रीन पार्टियों के बीच *ग्लोबल ग्रीन चार्टर* को बढ़ावा देने तथा समान विचार वाले समूहों तथा समाज के बीच वैश्विक महत्व के मुद्दों पर कार्रवाई करने तथा दुनियांभर में ग्रीन पार्टियों तथा संघों के बीच आपसी संवाद को गहराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज 24 देश *ग्लोबल ग्रीन* में शामिल हैं और जल्द ही अनेक अन्य पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं। *ग्लोबल ग्रीन* का कोई अध्यक्ष या सचिवालय नहीं है। इसके संयोजन का कार्य संचालन समिति के 12 सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

3. नए आंदोलन, नयी एजेंसिया

इस प्रकाशन में भूमंडलीय पार्टियों पर बातचीत अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक बहाना भर है। हम संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, अस्मिता, ऐतिहासिक अनुभव/स्मृतियों पर ध्यान देने की जरूरत पर बल देते हैं और साथ ही स्वायत्तता और स्वशासन की आकांक्षा के विश्वव्यापी होने को भी स्वीकार करते हैं।

मजेदार बात यह है कि इस पुस्तिका में योगदान करने वाले लोग वैश्विक राजनीतिक पार्टियों या नयी भूमंडलीय एजेंसियों के उदय की संभावना को स्वतः स्फूर्त ढंग से विश्व सामाजिक मंच² प्रक्रिया से जोड़कर देखते

2पहले विश्व सामाजिक पंच का आयोजन 2001 में पोर्तो अलेग्रे, ब्राज़ील में जनवरी 2001 में हुआ था। अधिक जानकारी के लिए

हैं। क्या इस प्रक्रिया में भूमंडलीय पार्टी का बीजरूप छिपा हुआ है ? इसके ठीक विपरीत विश्व सामाजिक मंच के दौरान आयोजित हमारी बातचीतों में भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के विचार को कुछ खास तरजीह नहीं मिली। बल्कि लोगों ने इस विषय में अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त कीं। कई लोगों को यह अंदेशा था कि भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों का विचार दरअसल यूरोप-केंद्रित हैं और भविष्य में पैदा होने वाली इन पार्टियों पर दुनियां भर के समृद्ध और शक्तिशाली लोगों का प्रभुत्व रहेगा। यह अवश्य ही सोचने की बात है कि इस प्रकार की भूमंडलीय राजनीतिक पार्टी किन विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करेगी ?

अकादमिक अर्थों में नागरिक समाज के आंदोलनों तथा राजीतिक दलों में यह अंतर है कि ये आंदोलन सार्वजनिक नियामक संस्थाओं पर बिना कब्जा किए सामाजिक कायदों को एक खास रूप देना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सार्वजनिक शासकीय केंद्रों पर अधिकार करना है। लोकप्रिय आंदोलन तथा गैर-पार्टीगत संघों की रूचि चुनाव जीतने में नहीं होती। परिणामस्वरूप, इन बहसों से निकलने वाली एक विचार श्रृंखला यह सवाल खड़ा करती है कि इन नए राजनीतिक आंदोलनों को निरूपित करने के लिए इन्हें 'राजनीतिक एजेंसी' के रूप में देखना बेहतर होगा न कि परंपरागत राजीतिक पार्टी के रूप में।

कानूनी दृष्टि से भी अलग-अलग देशों में नागरिक समाज के संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत करने के तरीके अलग-अलग हैं। कुछ देशों में नागरिक समाज के संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण एक ही संस्था के द्वारा होता है जबकि अन्य देशों में इसके लिए अलग-अलग व्यवस्था है। इसके कारण सांस्कृतिक तथा समाजशास्त्रीय विभिन्नताओं का सवाल खड़ा होता है।

अगर विश्व सामाजिक मंच प्रक्रिया के दौरान भूमंडलीय राजनीतिक दलों के विचार को समर्थन नहीं मिलता है तो फिर प्रतिभागी किस विचार का समर्थन करते हैं। छः साल पुरानी इस प्रक्रिया का नारा है 'दूसरी दुनियां संभव' है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि यह दुनियां कैसे बनायी जाए ? परंपरागत रूप में वामपंथ राज्य सत्ता पर कब्जा करने के विचार से प्रेरित रहा है। विश्व सामाजिक मंच -V के पोर्तो अलेग्रे अधिवेशन (2005) के दौरान ताइवो ताइवेनन तथा जॉन होलोवे के बीच तीखी बहस हुई कि क्या आगे बढ़ने के लिए राज्य सत्ता पर कब्जा करना आवश्यक है ? होलोवे के अनुसार नागरिक समाज को राज्य सत्ता पर अधिकार करने की जरूरत नहीं है जबकि ताइवेनन का कहना था कि दुनियां को बदलने की बात बेमानी है यदि इसके लिए राज्य सत्ता पर अधिकार न किया जाए। ताइवेनन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि परंपरागत राजनीतिक पार्टियों के मॉडल से हटकर भी राजनीतिक एजेंसियों का अन्य स्वरूप हो सकता है। होलोवे के द्वारा दिए गए प्रभावशाली नारे 'बिना सत्ता पर काबिज हुए दुनियां का लोकतंत्रीकरण संभव नहीं है' का जवाब होगा कि सत्ता पर काबिज होने का अर्थ सिर्फ राज्य पर अधिकार करना नहीं है। लोगों को अधिकार' और 'लोगों पर अधिकार' के अंतर्दृष्टिपूर्ण विभाजन का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता जिसके अंतर्गत लोगों की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति के लिए संस्थागत व्यवस्था (जिसमें कुछ समूह व्यवस्था के नियमों पर

कुछ अधिकार रखते हैं) की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह संभव है कि लोगों के ऊपर अधिकार की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में क्रांतिकारी ढंग से अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनायी जाए। मजेदार अवधारणा नयी राजनीतिक एजेंसियां (एजेंसी नहीं) है। ये राजनीतिक एजेंसियां वैकल्पिक संरचनाएं बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, न कि राज्य सत्ता पर। यही संरचनाएं कालक्रम में लोकतांत्रिक शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित होंगी। लेकिन इन राजनीतिक एजेंसियों का स्वरूप कैसा होगा ? ये कैसा आकार ग्रहण करेगी? भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों का विश्व राजनीति के लिए क्या अर्थ होगा या होना संभव होगा ?

4. राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत और एजेंसी

भूमंडलीय राजनीतिक कार्रवाई या पार्टी कार्यक्रम पर बातचीत करने के पहले राजनीतिक परिवर्तन की कुछ परंपराओं और दिशाओं के बारे में थोड़ी चर्चा उचित रहेगी। नवउदारवादी प्रभुत्व के इस दौर में लोकप्रिय आंदोलनों के उद्गम तथा विकास को प्रेरणा देने वाले 19वीं तथा 20वीं सदी के कुछ विचारकों के बारे में बात करना समीचीन होगा।

डेविड हार्वे (2005) ने अपनी किताब 'ए-ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियोलिबरलिज्म' में इस बात की व्याख्या की है कि किस प्रकार 1970 के दौर से ही अधिकांश विश्व में नवउदारवादी चिंतन और कार्यशैली हावी हो गयी है। हार्वे इस सफलता की व्याख्या अंशतः राज्य शक्तियों के पुनर्निर्माण के रूप में करते हैं जिसके अनुसार निजीकरण, वित्त तथा बाजार की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है जबकि अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को घटाने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही हार्वे नवउदारवाद को कुलीन वर्गों की एक प्रतिक्रांति के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य जनता के ऊपर नियंत्रण और अधिकार प्राप्त करना है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी पार्टियां दरअसल एक भूमंडलीय राजनीतिक कार्यक्रम के अनुरूप कार्यरत रही हैं और इस कार्यक्रम को दुनियां भर में व्यापक तौर पर लागू किया गया है।

1989 में शीत युद्ध की समाप्ति दक्षिणपंथ तथा नवउदारवाद की सफलता का एक कारक या शायद मौलिक कारण कहा जा सकता है। शीतयुद्ध के दौरान पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच मौजूद धुवीकरण के कारण राजनीतिक दिशाओं के बारे में या इन दो प्रभुत्वशाली विचारधाराओं के मिश्रित स्वरूप के बारे में बहस होती थी। आज जब हर तरफ पूंजीवाद ने जड़ें जमा ली है तो किसी भी प्रकार के विकल्प चाहे वह साम्यवादी हो, गांधीवादी हो या कुछ अन्य हों के साथ संवाद की गुंजाइश नहीं है। दुनियां भर में यह मान्यता व्याप्त हो चुकी है कि पूंजीवाद ही सभी प्रकार के विकास का स्रोत है तथा प्रतिस्पर्धा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ ही एक सुरक्षित तथा समृद्ध विश्व की गारंटी है। इसके पीछे केन्द्रीय विचार यह है कि मुनाफा खुद व खुद रिस रिस कर गरीबों के पास पहुंचता है क्योंकि व्यवस्था को भी उनके योगदान की जरूरत है। धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है ताकि वो पूरी तरह से बर्बाद न हो जाएं। आज का राजनीतिक संतुलन दक्षिणपंथ की

ओर झुका हुआ है इसीलिए राजनीतिक परिवर्तन की मांग सबसे ज्यादा वामपंथ से ही आती है।

वामपंथी राजनीतिक समूहों के बीच, सामाजिक लोकतांत्रिक सुधारवाद (जो कि इन बहसों का एक मजबूत सिद्धांत है) के अलावा नवउदारवाद के विकल्प के निर्माण की दृष्टि से परिवर्तनकारी राजनीतिक विचारों की कम से कम चार धाराएं मौजूद हैं – (1) कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स (2) एंटोनियो ग्रामशी (3) मोहनदास करमचंद गांधी तथा (4) एच.जी. वेल्स ।

इनमें से पहली धारा की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। उस समय समता मूलक क्रांतिधर्मी विचारों की रूपरेखा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मिली थी। 1840 के दशक में मार्क्स और एंगेल्स ने सोचा कि औद्योगिक ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में अन्य स्थानों पर क्रांति न केवल अवश्यभावी थी बल्कि आसन्न भी। लेकिन 1848 के ठीक बाद मार्क्स और एंगेल्स इस बात से आश्वस्त हो गए कि 'नयी क्रांति नये संकट से ही पैदा होगी'। मार्क्स ने अपना ध्यान राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर लगाना शुरू कर दिया ताकि भविष्य के राजनीतिक आर्थिक संकट के कारणों और परिस्थितियों को समझा जा सके। दीर्घकालीन आर्थिक प्रक्रियाओं का सिद्धांत विकसित करते हुए (जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह संकट मुनाफे की दर को घटाएगा और औद्योगिक पूंजीवाद को नष्ट कर देगा) वह *प्रथम इंटरनेशनल* में भी सक्रिय थे और इसकी शुरुआत में 1864 में इसकी साधारण सभा के लिए भी चुने गए थे। मार्क्स और एंगेल्स की परंपरा में काम करने वाले लोग इन प्रयत्नों तथा अनुभवों से प्रेरणा लेते हैं। इसके पीछे पूंजीवाद के अंदर शोषित वर्ग या वर्गों के लोगों को लामबंद करने की अनवरत चाहत (दुनियां के मजदूरों एक हो) ही काम कर रही थी। लेकिन इस दुष्ट पूंजीवादी समाज व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही इसकी चिंता का केंद्रीय विषय रहा है न कि एक बेहतर समाज की परिकल्पना या निर्माण। भविष्य में संभव होने वाली वर्गहीन और शायद राज्यहीन सामाजिक व्यवस्था, जो उत्पादन के साधनों की सामूहिक मिल्कियत और निजी-संपत्ति के अभाव पर आधारित होगी – की परिकल्पना बड़े ही धुंधले ढंग से और तरल रूप में की जाती है। कई बार ऐसी भी मान्यता रही है कि हिंसा क्रांतिकारी परिवर्तन का जायज अंग है।

एंटोनियो ग्रामशी 20वीं सदी का इटली का कम्युनिष्ट था जिसने बाद में 1917-18 की रूसी क्रांति के कुछ पहलुओं, खासकर एकपार्टीवादी लेनिनवादी विचार का विरोध किया। हालांकि इटली की फासीवादी पुलिस द्वारा 1926 में गिरफ्तार किए जाने के पहले तक ग्रामशी ने मॉस्को के साथ सहयोग किया था। दस वर्ष लंबे अपने जेल-प्रवास के दौरान ग्रामशी ने 30 नोटबुक और इतिहास की व्याख्या संबंधी 3000 पेज लिखे। जेल से छूटने के तुरंत बाद 1937 में ग्रामशी की मौत हो गयी। अपने नोटबुकों में ग्रामशी ने प्रभुत्व, सामान्य सूझबूझ, नागरिक समाज, मीडिया, शिक्षा तथा बुद्धिजीवियों के दायित्व के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये नोटबुक पाश्चात्य मार्क्सवाद में काफी प्रभावशाली रहे हैं। अन्य बातों के अलावा ग्रामशी का तर्क था कि क्रांतिकारी पार्टी ही *आधुनिक युवराज* है और यही वह शक्ति है जो श्रमिक वर्ग को जमीन से जुड़े बुद्धिजीवी पैदा करने और नागरिक समाज के भीतर एक वैकल्पिक प्रभुता यानी बौद्धिक नेतृत्व पैदा करने का अवसर प्रदान करेगा। शायद उनका अंतिम उद्देश्य एक प्रकार के क्रांतिधर्मी लोकतंत्र या स्वायत्त नागरिक समाज की रचना थी जिसमें स्वतः नियंत्रण की क्षमता होगी।

लेकिन ग्रामशी पूंजीवाद के इस विकल्प की संस्थागत रूपरेखा के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं रखते थे। प्रायः ग्रामशी को कार्याधारित विचार का दार्शनिक माना जाता है जिन्होंने संस्कृति की लोकतांत्रिक राजनीति, शिक्षा और मिथकों की लामबंदी पर जोर दिया। हालांकि लोकतांत्रिक सिद्धांत ही ग्रामशी की विरासत माने जाते हैं, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके संबंध अब भी विवादास्पद हैं।

गांधी, ग्रामशी से करीब दस साल ज्यादा जीवित रहे। उनकी हत्या 1948 में एक हिंदू आतंकवादी ने कर दी। वह अपने दर्शन *सत्याग्रह* के लिए प्रसिद्ध हैं। अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह का अर्थ है नागरिक अवज्ञा या सिविल नाफरमानी। गांधी जी विशेष रूप से आत्मालोचना के पक्षधर थे और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते थे। सत्य, प्रेम और अहिंसा की परम शक्ति में विश्वास रखते थे। “मैं जब निराशा से घिर जाता हूँ, मैं इस बात का स्मरण करता हूँ कि इतिहास में हमेशा सत्य और प्रेम विजयी हुआ है। दुनियां में आततायी और हत्यारे हुए हैं जो थोड़े समय के लिए अपराजेय लगते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन होता है। इसे हमेशा याद रखना”³। गांधी ने विविधतापूर्ण तरीके से विभिन्न धर्मों तथा परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण की और उन्हें एक नया स्वरूप दिया। अपने समकालीन उत्तरी गोलार्द्ध के मार्क्सवादियों की तरह गांधी भी पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था के गंभीर आलोचक थे। लेकिन उन्होंने जो विकल्प प्रस्तुत किया वह भारत के छोटे व स्थानीय समुदायों की सरल तकनीकों और आचरणों पर आधारित था। उदाहरण के लिए सफाई का सवाल उनके लिए बहुत ही महत्व रखता था। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से भारत को बहुत ही कम खून खराबे में आजाद करवाने में गांधी के सत्याग्रह की निर्णायक भूमिका रही थी। हालांकि स्वतंत्र भारत के संविधान में गांधी के चिंतन संबंधी कई तत्व शामिल हैं लेकिन आधुनिक आजाद भारत ने अहिंसा, सादा जीवन और स्थानीयता के महत्व संबंधी उनके विचारों का पालन नहीं किया है, न ही पूंजीवाद और आधुनिकता की उनकी आलोचना में शामिल हुआ है। लेकिन उनके उदाहरण और सोच ने दुनियां भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान की है।

एच जी वेल्स गांधी से तीन साल बड़े थे और उनकी मृत्यु 1946 में हुई। वह 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में सक्रिय सही अर्थों में वैश्विक चिंतकों में से एक थे। हालांकि उनकी ख्याति खासकर उनके विज्ञान-गल्प पर आधारित उपन्यासों *दि वॉर ऑफ वर्ल्ड्स* और *दि इनविजिबुल मैन* के कारण है, वह एक मुखर समाजवादी तथा अनेक राजनैतिक एवं वैचारिक नीतियों के रचयिता थे। वह कभी कभी *फ़ैबियन सोसायटी* तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी के कार्यकलापों में भी भाग लिया करते थे लेकिन प्रायः उनका टकराव ब्रिटेन के *सोशल-डेमोक्रेसी* के साथ होता रहता था। उनका सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी राजनीतिक आदर्श था *विश्व-राज्य* की परिकल्पना। विनाश की नयी शक्तियों और तकनीकों के बीच मानवता का दीर्घकालीन अस्तित्व वेल्स की सबसे बड़ी चिंता थी। लेकिन उनका यह भी सोचना था कि मानवता की संभावनाओं और महानता का विकास एक *विश्वनगर* में ही संभव था। हालांकि अपने जीवन काल में वेल्स के राजनीतिक विचारों को सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण विचारों को जन्म दिया जिनमें से कई तो अपने समय से आगे थे। *ओपन कंसपिरेसी* (1933) में वेल्स ने विश्व की एकता

3कोट डी.बी. <http://www.quotedb.com/quotes/1914>

के लिए एक बहुलतावादी जनांदोलन की परिकल्पना की है जो अंततः एक विश्वराज्य का निर्माण करेगा। हालांकि 'ओपेन कंसपिरेसी' कुछ अर्थों में 2000 के पूर्वार्द्ध के भूमंडलीय नागरिक समाज और विशेष कर विश्व सामाजिक मंच प्रक्रिया की झलक दिखलाता है, यह एक गहरे अर्थ में 'जन आंदोलन' है। इसका निर्माण, कम से कम अंशतः साझी भूमंडलीय समझ से होती है जिसकी शुरुआत वेल्स द्वारा किए गए वैश्विक धर्म, इतिहास और मानवता की संभावनाओं के वैश्विक मानवतावादी निरूपण से होती है। एक गैर-मानव केंद्रित धर्म विकास में विश्वास रखती है और मानव प्रजाति की 'आत्मा इस बात में निहित है कि यह उसके जन्म के पहले से मौजूद है और उसके गुजरने के बाद भी मौजूद रहेगा। वेल्स इस नए आंदोलन के प्रति एक प्रकार की अर्द्ध-धार्मिक भक्ति की मांग करते हैं। वेल्स का विश्वास था कि सच्चे अर्थों में समर्पित व्यक्तियों तथा समूहों का जन आंदोलन ही ज्ञान आधारित और शायद लोकतांत्रिक विश्व संगठन का निर्माण करने में सक्षम होगा। 'ओपेन कंसपिरेसी' की सबसे अलहिदा बात है कि वेल्स ने इस किताब में आंदोलन के विविध प्रतिभागियों की जो परिकल्पना की है उसमें कम्युनिष्ट पार्टियों तथा मजदूर आंदोलन के अवशेषों से लेकर, प्रगतिशील बैंकर, पेशेवर तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं धार्मिक संस्कृतियों के लोग शामिल हैं।

5. तर्कों पर एक गहन दृष्टि

क्या हम भूमंडलीय संसद या भूमंडलीय सरकार की चर्चा किए बिना भूमंडलीय पार्टियों की बात कर सकते हैं? यह मान्यता सहज रूप से सही प्रतीत होती है लेकिन इसके ठीक विपरीत हाइकी पाटोमाकी तथा ताइवो ताइवेनेन (2006 : 26, 181) ऐसा नहीं मानते कि भूमंडलीय पार्टियां राष्ट्रराज्य के अस्तित्व या दायित्व को नकार कर ही परिकल्पित की जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय शासन की अधिक वैध और लोकतांत्रिक एवं खुलेपन वाली प्रक्रिया अपनायी जाय, बजाए इसके कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों की संस्थाओं की नकल वैश्विक स्तर पर की जाय। अलबत्ता वैश्विक स्तर पर इसे करना संभव भी नहीं है।

पाटोमाकी तथा ताइवेनेन का निष्कर्ष है कि भूक्षेत्रीयता और इसके परिणामों का विरोध करने से बेहतर है कि जिस प्रकार आधुनिक समाजों ने प्रारंभ में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के नए स्वरूपों का इजाद किया, हम भी 21वीं सदी में लोकतांत्रिक प्रतिभागिता, प्रतिनिधित्व तथा जवाबदेही के नए स्वरूपों के लिए काम करें। शोध के इस सवाल में विभिन्न प्रकार के विश्व राजनीतिक संदर्भों की सही व्याख्या शामिल है। इसके साथ ही वैश्विक संस्थागत व्यवस्थाओं के ठोस मॉडलों की व्यावहारिकता और वास्तविक परिणामों के बारे में विचार करना होगा जिसमें पुनर्नियमन, कराधान, पुनर्वितरण तथा भूमंडलीय आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय योजनाओं का निर्माण शामिल है। संदर्भों के अनुरूप संस्थागत जरूरतों की हमारी संभावित एवं वांछित व्याख्या भी बदलनी चाहिए। जैसा कि जैन आर्ट स्कोल्ट (2006 : 50, 57) कहते हैं कि आज के वैश्विक समय के साथ नहीं चल पाने के कारण राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक प्रभाव काफी घट गया है। वह आगे कहते हैं कि भूमंडलीकरण के साथ ही शासन की विधा राज्यवाद से बहुकेन्द्रक शासन व्यवस्था या विश्व-व्यवस्था की तरफ झुकी है। नागरिक समाज और सरकारी क्षेत्रों ने भी इसी के अनुरूप अपनी गतिविधियों को ढाल लिया है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल अब भी "राज्यवादी

भूक्षेत्रवादी, राष्ट्रवादी कार्यशैली से ही चिपके हुए हैं। (वही : 51) उत्तर-राज्यवादी शासन विधा में यह आवश्यक है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को अपनी सामयिकता और 21वीं सदी में लोकतंत्रीकरण की अपनी क्षमता को बचाए रखना है तो उन्हें अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। स्कोल्ट का मानना है कि अब तक राजनीतिक पार्टियां भूमंडलीय नीति संबंधी मुद्दों के बारे में जनता की समझदारी और विचार-विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ाने में असफल रही हैं। नागरिक समाज के संघों के विपरीत, देश-आधारित राजनीतिक पार्टियां देश के बाहर की शासकीय संस्थाओं से जुड़ने में असफल रही हैं। इसलिए तात्कालिक दृष्टि से देश – राज्य – राष्ट्र की सीमाओं से बाहर भूमंडलीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या भूमंडलीय पार्टियों की अपेक्षा अधिक संभावना दिखाई देती है। दूसरी तरफ गौरतलब है कि नागरिक समाज के संगठनों ने राजनीतिक पार्टियों से बहुत कम संबंध स्थापित किए हैं। वैश्विक मामलों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक पार्टियों को वैश्विक सामाजिक समता को बढ़ाने वाले संसाधनों के बंटवारे को प्रोत्साहन देना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि जब तक राजनीतिक पार्टियां भूक्षेत्रीय संगठन के रूप में शामिल रहते हैं और देश आधारित जनता के हितों की देखभाल भर करते हैं, यह समझना मुश्किल है कि किस प्रकार वैश्विक समता उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगी। आगे, स्कोल्ट चेतावनी देते हैं कि देश आधारित पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बावजूद उनके आपसी कार्य संबंधों को बढ़ाचढ़ा कर नहीं देखना चाहिए। वह इस बात का भी मूल्यांकन करते हैं कि राज्य की सीमाओं के बाहर देश आधारित राजनीतिक पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, क्षेत्रीय पार्टीगत संरचनाओं और स्पष्ट रूप से भूमंडलीय पार्टियों के द्वारा किस प्रकार राजनीतिक पार्टियों को पुनर्गठित किया जा सकता है। स्कोल्ट कहते हैं कि विश्वव्यापी शासकीय एजेंसियों से संबद्ध चुनावी प्रतिनिधि निकायों का निर्माण कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। वैश्विक स्तर पर चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होगा ? वैश्विक संसदों के लिए कौन सा चुनावी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ? एकाधिक महादेशों के बीच बैलटों का संचालन और उनकी देखरेख कैसे होगी तथा चुनाव प्रचार के लिए संसाधन कैसे मुहैया कराए जाएंगे ? स्कोल्ट का निष्कर्ष है कि आधुनिक काल में वैश्विक मामलों के शासन संबंधी मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक विचार-विमर्श की गहरी जरूरत है। लोकतंत्र के अभाव के कारण वर्तमान भूमंडलीकरण के खिलाफ गहन असंतोष पैदा हुआ है जो सड़कों पर हुए विशाल प्रदर्शनों तथा रोजमर्रा की बातचीत में दिखाई देते हैं। भूमंडलीकरण के शासन की लोकतांत्रिक जड़ें बहुत ही कमजोर रही हैं। इसके कई कारण हैं जैसे संस्थागत विफलता, संरचनागत गुलामी तथा भूक्षेत्र के बाहर की जनता को स्वीकार करने में कमी वगैरह।

स्टीफन गिल (2006 : 148) बताते हैं कि हमें इस धोखे से बचना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रतिपक्ष या प्रगतिशील शक्तियों को एजेंसी के एक खास रूप या पार्टी में एकीकृत करना चाहिए या करना संभव है। बल्कि जिसे बोलचाल की भाषा में भूमंडलीय नागरिक समाज कहते हैं और जिसका ठोस रूप विश्व सामाजिक मंच के दौरान दिखाई पड़ा, क्रिस्टोफर चेज डुन तथा एलेन रीस भूमंडलीय न्याय आंदोलन (2006 : 98) के अंदर चार प्रकार के विभाजनों को रेखांकित करते हैं। पहले दो खेमे उन लोगों के हैं जो अधिक आर्थिक विकास और

रोजगार सृजन की वकालत करते हैं और जो वर्तमान उत्पादन और उपभोग के स्तर में कटौती चाहते हैं। दूसरा खेमा भूमंडलीय उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच व्यापार, पुनर्वितरण, श्रम और पर्यावरण संबंधी मतभेदों में केंद्रित है जिसकी जड़ें विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर अलग-अलग सोच रखने के कारण बना है। क्या इन समूहों के बीच कोई साझा मंच है जहां एक भूमंडलीय पार्टी की स्थापना की जा सकती है ? अगर हम इसकी व्यापक परिभाषा लें तो चेज डुन तथा रीस के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था के अंदर पिछले कम से कम 400 वर्षों से अंतर्देशीय सामाजिक आंदोलन तथा वैश्विक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं। प्रतिभागियों की राय और सर्वे-शोध के आधार पर उन्होंने नागरिक समाज के अब तक के सबसे बड़े जमावड़े विश्व सामाजिक मंच में भाग ले रहे लोगों के बीच लोकप्रिय सामाजिक परिवर्तन की धारणाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट बनायी है। अपने आलेख में उन्होंने वर्तमान वैश्विक न्याय आंदोलन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है और इस सवाल पर लोगों की राय मांगी है कि क्या एक नया *इंटरनेशनल* उभड़ रहा है ? चेजडुन तथा रीस ने विश्व सामाजिक मंच के प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया है तथा अपने अध्ययन के दौरान यह पाया है कि प्रगतिशील शक्तियों को लामबंद करने की हाल की कोशिशों का उद्देश्य विश्व शासन और विश्व अर्थव्यवस्था के कार्य संचालन का लोकतंत्रीकरण है। कार्यकर्ता अतीत की गलतियों से बचते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं। चेज डुन और रीस इस बात पर जोर देते हैं कि इस नए प्रोजेक्ट को अंतर्देशीय सामाजिक आंदोलनों, विश्व क्रांतियों तथा वैश्विक शासन में पिछले 400 वर्ष में होने वाले क्रमिक विकास की रोशनी में तथा विश्व ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। चेज डुन और रीस खास कर इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या वर्तमान वैश्विक न्याय आंदोलन के आधार पर एक नयी समाजवादी पार्टी बनायी जा सकती है और यदि हां तो इस पार्टी को कैसे संगठित किया जाए और वैश्विक पार्टी निर्माण में हुई अतीत की भूलों से हम क्या सीख सकते हैं ? जैसे दुनियां भर में लोकतंत्रीकरण की इस तीसरी लहर के प्रभाव में लोकतंत्र फैल रहा है, आर्थिक और राजनीतिक भूमंडलीकरण ने राजनीतिक सत्ता के कार्यपथ को राष्ट्र राज्य से हटाकर वैश्विक स्तर पर ला छोड़ा है।

समीर अमीन एक नए-पांचवें *इंटरनेशनल* की अपील करते हैं (अमीन 2006 : 139, 141)। उनकी शर्त है कि इस *इंटरनेशनल* की परिकल्पना *प्रथम इंटरनेशनल* जैसी होनी चाहिए, न कि द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ *इंटरनेशनल* जैसी। अमीन का निष्कर्ष है कि पूंजी के खिलाफ लोगों के संघर्ष को इकट्ठा करने के लिए एक नए *इंटरनेशनल* की जरूरत है। 1848 तथा *वर्किंग मेन्स एसोशिएशन* से अलग हटते हुए, अमीन *इंटरनेशनलों* के 150 साल पुराने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं तथा रणनीतिक कार्यवाही के लिए उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट करते हैं। वह विभिन्न पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों को विविधता में एकीकृत करने के लिए रणनीति की मांग करते हैं। ज्यादा ठोस अर्थों में वह हर स्तर पर उदारवाद को वापस लेने-देश में और वैश्विक स्तर पर पृथ्वी के ऊपर फौजी नियंत्रण के अमरीकी और/या नाटो की फौजों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को वापस लेने और उन उदारवादी एटलांटिकवादी मान्यताओं को वापस लेने की मांग करते हैं जिनपर यूरोपीय संघ की संस्थाएं आधारित हैं। पांचवें *इंटरनेशनल* के

लिए उनके मौलिक सिद्धान्तों को निम्नलिखित दो परस्पर पूरक वाक्यों में व्यक्त किया जा सकता है – (1) लोकतंत्र के बिना समाजवाद संभव नहीं (और इसीलिए समाजवाद की ओर प्रगति बिना लोकतांत्रिक आचरण के हो ही नहीं सकती) तथा (2) सामाजिक विकास के बिना लोकतांत्रिक विकास संभव नहीं।

स्टीफन गिल स्कोल्ट भी इस बात का समर्थन करते हैं और चेतावनी देते हैं कि हमें अपने शोध को उस खास राजनीतिक स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए जिसे परंपरागत रूप से पार्टी कहा जाता है। (गिल, 2006: 150) वह स्वीकार करते हैं कि यह एक प्रकार की विसंगति है लेकिन जब हम राजनीतिक तथा नागरिक समाज के असली स्वरूप को देखते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है। गिल प्रस्तावित करते हैं कि हमें राजनीतिक एजेंसी को आंदोलनों के रूप में परखना चाहिए न कि संगठनों के रूप में।

1990 के दशक के उत्तरार्ध में नागरिक समाज की लामबंदी संबंधी अपने कथन के आलोक में 2000 ई. में गिल ने यह सवाल उठाया कि क्या एक नयी भूमंडलीय पार्टी बनने की प्रक्रिया जारी है ? गिल खासकर 'सीएटल की लड़ाई' का जिक्र करते हैं जबकि 1998 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रदर्शन हुए थे। छः साल बाद, स्टीफन गिल सुझाव देते हैं कि भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में हमारी समझ और शोध द्वि-द्वैतमक होना चाहिए जिससे उनका अर्थ यह है कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि स्थानीय प्रतिक्रियाओं के अलावा भूमंडलीकरण करने वाला कुलीन वर्ग भी है जो 'नव उदारवादी भूमंडलीकरण के विशेष स्वरूप को बढ़ावा देता है। इससे भी आगे बढ़कर गिल कहते हैं कि दुनिया में एक प्रकार का वैश्विक संविधान अस्तित्व में आ चुका है जिसके तहत 'राष्ट्रीय और अंतर्देशीय कानूनों और नियमों का जाल फैल चुका है जो नवउदारवादी पूंजी संचय के लिए आवश्यक कानूनी तथा न्यायिक ढांचे का निर्माण करता है'। गिल आगे कहते हैं कि इस कानूनी संरचना की गारंटी अमरीका और इसके करीबी फौजी सहयोगियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। उनका निष्कर्ष है कि विश्व संवैधानिक व्यवस्था की रचना करने की जरूरत नहीं है बल्कि विश्व शासन की विभिन्न संस्थाओं की प्रकृति और उद्देश्य को बदलने की जरूरत है ताकि मानवीय स्वतंत्रता और विविधता फल-फूल सके।

थॉमस वॉलग्रेन (2006 : 166) जोर देकर कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। लेकिन इधर पार्टियों ने लोकतंत्र के साधन के रूप में अपनी उपादेयता खोई है और इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक आकांक्षा और कार्य को पार्टियों की बजाय आंदोलनों से जोड़ना बेहतर समझा है। वॉलग्रेन हमारा ध्यान इस सवाल की ओर खींचते हैं कि भूमंडलीय न्याय आंदोलन की अभिव्यक्ति के रूप में पैदा हुई यह वैश्विक पार्टी संरचना उन खतरों से स्वयं को कैसे बचा सकती है जिसके कारण पुरानी तथा छोटे स्तर पर वैश्विक पार्टियां संकट में पड़ गयी है। लेकिन यह तस्वीर हमारी आंखों के सामने ही एक हद तक बदल रही है। पश्चिम के राजनीतिक इतिहास में जो पार्टियां प्रभुत्वशाली रही हैं उनका जन्म ताकतवर जन आंदोलनों से हुआ है। आज हमारे पास दो सामाजिक आंदोलन हैं जिनके जनाधार ने पिछले दो दशकों में राजनीतिक रूप से सफल पार्टी संरचनाओं को पैदा किया है। इनमें से एक पर्यावरण आंदोलन है जिसने ग्रीन पार्टियों को जन्म दिया है और दूसरा विदेशियों के भय पर आधारित तथा नस्लवादी आंदोलन है जिसने

अति-दक्षिणपंथी या नव-फासीवादी पार्टियों को जन्म दिया है। वॉलग्रेन प्रभुत्वशाली पार्टियों के अंदर घटित परिवर्तन की भी चर्चा करते हैं जो वैश्विक आंदोलन आधारित अपनी पहचान से हटकर खुद को राष्ट्रीय व्यावहारिक इकाइयों में बदल रही हैं तथा जिनका लोकतांत्रिक जीवन एक प्रकार के अंतःविस्फोट के लक्षण दिखा रहा है। वॉलग्रेन आगाह करते हैं यह सोचना हमारे समय की एक बहुत बड़ी भूल होगी कि अगर हम इस नारे पर चलें कि 'राष्ट्र-राज्य आर्थिक भूमंडलीकरण के बोझ से दबे जा रहे हैं और इसीलिए हमें और भी अधिक वैश्विक शासन की जरूरत है, तो लोकतंत्र और न्याय सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे।

आखिर में वॉलग्रेन वैश्विक लोकतांत्रिक शासन के साधनों की स्थापना को बढ़ावा देने में निहित एक मौलिक खतरे की भी चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि इन प्रस्तावों को राजनीति की मुख्यधारा स्वीकार कर लेगी तथा उन्हें वैश्विक शासन के पूर्णतः अलोकतांत्रिक चरित्रवाले साधनों में बदल देंगी। यह पाटोमाकी तथा ताइवेनेन द्वारा प्रस्तावित *सी टी टी ओ* पर भी पूरी तरह लागू होती है।

विजय प्रताप हमें यूरोप-केंद्रीयता (2006:172) के बारे में आगाह करते हैं । विजय प्रताप इस बात को रेखांकित करते हैं कि पश्चिम और खासकर यूरोपीय संघ में जो कुछ भी किया जाता है उसे वैश्विक करार दिया जाता है । कई बार तो यह नस्लवादी भी होता है । वह राष्ट्रीय को भूमंडलीय करार देने के बारे में भी हमें सचेत करते हैं । आज के समय में, भूमंडलीय पार्टियों का विचार यूरोप-केंद्रिक या उत्तरगोलार्द्ध-केंद्रिक है । पार्टी व्यवस्था का अर्थ दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग-अलग होता है । उदाहरणस्वरूप दक्षिण एशिया में सभी पार्टियां हाशिए पर धकेल दी गई है । आखिरकार भूमंडलीय पार्टी या पार्टियां किस के हित का पोषण करेंगी ? उनका राजनीतिक एजेंडा कैसा होगा ? अगर हम दुनिया के पैमाने पर सरकार की बात करें तो यूरोपीय संसद से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ? निश्चय ही यूरोपीय संसद क्षेत्रीय स्तर पर नीति- निर्माण के अग्रणी प्रयत्नों में गिना जाता है । इसका अनुभव भी यही है कि मतदाता यूरोपीय संघ से अपना जुड़ाव महसूस नहीं करते और उनकी संस्थाएं नागरिकों से सुदूर महसूस होती है । प्रताप पूछते हैं कि वैश्विक संसद के कार्यकलापों की दृष्टि से इस क्षेत्रीय प्रयोग का क्या अर्थ है?

हैकी पाटोमाकी तथा ताइवो ताइवेनेन इस निष्कर्ष के साथ अपना आलेख समाप्त करते हैं कि 20वीं सदी में नवउदारवाद की ओर विकास के लिए जो प्रक्रियाएं और संस्थाएं जिम्मेवार हैं उनमें से कई अपनी प्रवृत्ति में अंतर्देशीय तथा भूमंडलीय हैं (2006:183)। उसके जवाब के तौर पर विश्व इतिहास के इस खास दौर में वह राजनीतिक कल्पनाशीलता तथा विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवहारों, परिस्थितियों तथा संभावनाओं के बारे में नए ढंग की सोच की मांग करते हैं। उनके खाके के अनुसार ऐसा नहीं है कि भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियां नवउदारवादी होने के लिए शापित हैं बल्कि हमारा भविष्य नई चीजों को कल्पना करने तथा उन्हें बनाने की मानवीय सृजनात्मक क्षमता पर निर्भर करता है ।

6. आगे की बातचीत, शोध और कार्य के विषय में विचार

हमने भविष्य में राजनीतिक पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं से संबंधित शोध और बातचीत के एजेंडा के तौर पर चार प्रारंभिक सवालों की पहचान की है। पहला सवाल इस बात से संबंधित है कि नागरिक समाज और राजनीतिक आंदोलनों में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? दूसरा सवाल है कि विचारधाराओं के साथ क्या हो रहा है? खासकर हम प्रभुत्ववादी नवउदारवादी विचार संरचना तथा अधिक टिकाऊ विकल्पों को माननेवाले लोगों के बीच घट रही अंतःक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा, हम यह देखना चाहते हैं कि पार्टी व्यवस्था राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तरों पर किस प्रकार विकसित हो रही है और चौथा कि राजनीतिक पार्टियों तथा पार्टी व्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय पहलू तथा उनकी संभवनाएं क्या हैं?

1. आंदोलन आधारित पार्टियों— वामपंथी, दक्षिणपंथी तथा धार्मिक— वामपंथ के बीच यह एक साझी दृष्टि और आकांक्षा है कि जनान्दोलनों का विकास परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति के रूप में होगा जो राज्यसत्ता पर काबिज होगी या कम से कम राज्य और बाजार की प्रकृति को प्रभावित करेगी ताकि स्वतंत्रता, भाईचारा तथा समता के आदर्शों को साकार किया जा सके। कुछ लोगों के लिए रूस, चीन, वियतनाम आदि में हुई कम्युनिष्ट क्रांति इस बात को प्रमाणित करती है। कुछ अन्य लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लोकतांत्रिक समाजवादियों या हाल के वक्त में लैटिन अमेरिका के अनुभव को इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये लोग लैटिन अमेरिका के अंदर *सबकमांडेंट मार्कोस* तथा *जैपतिस्ता* के मैक्सिको में, लूला तथा पी.टी के ब्राजील में और हाल में इवो मोरालेस तथा *मूवीमेंटो अल सोशलिज्मों* के बोलीविया में किये गये प्रयत्नों को दुनियाभर के वामपंथ के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में पेश करते हैं।

लेकिन हम सामाजिक आंदोलनों के वर्तमान माहौल को देखें तो अब भी वामपंथ जमीन पर प्रभुत्वशाली भूमिका से काफी दूर हैं। हाल की क्रांतियां या चुनावी जीतें बिलकुल अलग दिशाओं की ओर इशारा करती हैं। शायद 1979 ई. की ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने ही पिछले दशकों में पश्चिमी पूंजीवादी प्रभुत्व को मौलिक चुनौती दी है। फिलिस्तीन के चुनाव में *हमास* की विजय तथा लेबनान की सरकार में *हेजबुल्ला* का शामिल होना इस्लाम पर आधारित राजनीतिक आंदोलनों तथा संस्थाओं की चुनावीतंत्र में जीत के ताजा उदाहरण हैं। टर्की तथा इंडोनेशिया में धर्म आधारित राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

लेकिन नये तथा विकासमान राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करने वाला सिर्फ इस्लाम ही नहीं है। भारत में 1998–2004 के बीच हिन्दू कट्टरवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफी राजनीतिक समर्थन हासिल किया है जिसके कारण इससे संबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमेरिका में धर्म परिवर्तनवादी ईसाई आंदोलन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो करीब करीब प्रभुत्वशाली स्थिति में आ चुकी हैं। यूरोप में तो ईसाई पार्टियों के प्रतिनिधि शासकीय स्थानों पर सामान्यतया पाये जाते हैं।

यूरोप में 1980 के दशक में ग्रीन पार्टियों के उदय के बाद विदेशियों के भय पर आधारित दक्षिणपंथी पार्टी ही

हाल के वर्षों में सामने आने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी तथा बेल्जियम के चुनावों में उनकी उथल पुथल लाने वाली जीत एक बड़ी घटना है जिसे रेखांकित करने की जरूरत है। चाहे हमें उनके विचारों से जितनी भी असहमतियां हों, उन्हें लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है और वह भी एक प्रकार के आंदोलन ही हैं।

2. प्रभुता प्राप्ति के लिए विचारधारात्मक संघर्ष—धर्म प्रेरित इन पार्टियों और आंदोलन को अस्मिता प्रेरित कहा जाता है न कि विचारधारा प्रेरित। इस विभाजन पर बहस की गुंजाइश है क्योंकि धार्मिक आधार पर बनायी गयी राजनीतिक सोच भी एक प्रकार की विचारधारा ही है। पुरानी, विचारधारा आधारित वामपंथी पार्टियाँ भी कामगारों, किसानों तथा प्रगतिशील विचारकों की अस्मिता के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रही है।

इसी प्रकार सरकार में शामिल होते ही जिस नवउदारवादी राजनीति का पालन करती हुई सभी पार्टियाँ दिखाई देती हैं वह भी एक विचारधारात्मक संरचना ही है जिसे पक्षपातपूर्ण बुद्धिजीवियों ने निर्मित किया है और जिसके पीछे वित्तीय पूंजी और बड़ी-बड़ी कंपनियों की शक्ति लगी हुई है। इस दृष्टि से पार्टियां सदा की तरह आज भी विचारधारात्मक हैं केवल विचारधाराओं के मूल्यों, हितों तथा उद्देश्यों में अंतर आया है।

पिछले भाग में हमने इतिहास के कुछ ऐसे विचारकों की चर्चा की है जो आज भी लोकप्रिय हैं तथा जिनमें नवउदारवाद के विकल्प के कुछ तत्त्व खोजे जा सकते हैं। मार्क्स, गाँधी, ग्रामशी और वेल्स के अलावा भी अतीत और वर्तमान में अनेक ऐसे विचारक हैं जिनसे समाजवादी—पर्यावरणवादी राजनीति को प्रेरणा मिलती है। लेकिन उनपर बात करना इस आलेख की सीमाओं के अंदर संभव नहीं है।

3. परिवर्तनशील पार्टी व्यवस्था—कई क्षेत्रों में पार्टी व्यवस्था तेजी से बदलती हुई दिखाई देती है। चुनावपूर्व गठबंधनों के कारण उन स्थानों पर भी द्विदलीय व्यवस्था बन रही है जहाँ पहले बहुदलीय व्यवस्था थी। यह एक नयी परिघटना है। उदाहरण के तौर पर इस साल इटली तथा स्वीडन में ऐसा हुआ है।

पार्टियों को वित्तीय सहायता का राजनीति पर गहरा असर होता है। हालाँकि अधिकांश देशों में कुछ न कुछ नियम होते हैं लेकिन व्यवहार में बिना किसी सजा के इनसे आसानी से बचा जा सकता है या इन्हें तोड़ा जा सकता है। इसके कारण चुनावी खर्चों के लिए पार्टियों की निजी स्वार्थों तथा कॉर्पोरेशनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यह संबंध या कहें सांठ गांठ लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है।

चुनावों का बढ़ता खर्च व्यावसायिक मीडिया में जनसंचार और प्रचार पर निर्भर करता है। अन्य उत्पादों की तरह वोट भी खरीद बिक्री की वस्तु हो गयी है जिसे प्रचलित व्यावसायिक चैनलों के द्वारा खरीदा-बेचा जाता है। यह काफी मंहगा होता है और इसका प्रभाव मीडिया-घरानों से संबंध पर भी पड़ता है। जो पार्टियां कॉर्पोरेशनों से भारी-भरकम रकम प्रचार के लिए उपलब्ध करा सकती हैं उन्हें बेहतर प्रचार मिलने की संभावना रहती है।

अब तो बहुत ही कम पार्टियाँ ऐसी हैं जो पाठकों के पैसे से अपना अखबार चलाती हैं। इसलिए उनके विचारों की अभिव्यक्ति और उन पर बहस के लिए व्यावसायिक कॉर्पोरेट मीडिया ही सार्वजनिक स्थान उपलब्ध करवाता

है। कुछ देशों में यह काम राज्य प्रायोजित सार्वजनिक प्रसारण कंपनियां भी करती हैं। इसके साथ ही मीडिया कंपनियां विशाल, मुनाफा-प्रेरित संगठन बन चुकी हैं जिनकी अभिरुचि तथ्यात्मक पत्रकारिता या सार्वजनिक हित की रिपोर्टिंग में घटती जा रही है। मीडिया के इस परिवेश में पार्टियों के बीच का अंतर घटता जा रहा है और सभी पार्टियाँ एक ही तरह के लोगों की और एक ही तरह के एजेंडा के बारे में बात करती रहती हैं। वह अपना परंपरागत आधार तो बरकरार रखती हैं लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्हें अस्थिर मध्यवर्ती मतदाताओं की जरूरत होती है।

4. राजनीति तथा पार्टी व्यवस्था के अंतर्देशीय पहलू— *एन आई जी डी* का यह प्रोजेक्ट एक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ परंतु इसमें राष्ट्रीय परिदृश्यों पर भी बातचीत हुई जहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ दरअसल क्रियाशील रहती है। वैश्विक शासन तंत्र अस्तित्व में आ चुका है और इसके पीछे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व व्यापार संगठन की मजबूती आर्थिक तिकड़ी के साथ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की फौजी शक्ति मौजूद है।

यह आश्चर्यजनक है कि लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा वैश्विक शासन संबंधी मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों के बीच कितनी कम चर्चा होती है। लोग इस बात को सहज ही स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र-राज्यों के लिए एक प्रकार के लोकतांत्रिक सिद्धांत उचित हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ अलग या इसके ठीक विपरीत सिद्धांत लागू होते हैं।

यह विरोधाभास और भी चिंताजनक हो जाता है जब हम पाते हैं कि अधिकाधिक शक्तियां राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित हो रही हैं। वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे (विशेषकर यूरोपीय संघ में) आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी समझौतों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि संप्रभु जनता के हितों से बस कहने भर का मतलब रखती है।

इस खाई को पाटने के लिए नागरिक समाज के संगठनों द्वारा कुछ विशिष्ट प्रयत्न किए गए हैं। हमने विश्व सामाजिक मंच के बारे में और इसके दौरान हुई बहसों की चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के लिए ऐसे अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। बार्सिलोना से कार्यरत *यूबन्टू*, *इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन* जिसने शुरूआती दौर में कई बहसों तथा कार्यवाहियों को जन्म दिया, *दि थर्ड वर्ल्ड फोरम फॉर अल्टरनेटिक्स* जिसने 2006 के प्रारंभ में बामाको अपील जारी किया, भारत का *वसुधैव कुटुंबकम* जो व्यापक लोकतंत्र के लिए गठबंधन की हिमायत करता है ऐसे ही कुछ संगठन हैं।

लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ इस तरह की बहसों में बमुश्किल ही दिखाई देते हैं। सवाल है कि क्या उन्होंने वैश्विक लोकतंत्रीकरण से संबंधित इन बहसों से बचने का जानबूझकर फैसला किया है या उनकी सदस्यता और संरचना के राष्ट्र केंद्रित होने के कारण ऐसा हो रहा है?

पहले भी वैश्विक राजनीतिक पार्टियाँ होती थी। इस शब्द की व्यापक व्याख्या के अनुसार *जेसुआइट* जैसे संघ

या आजकल दावोस में हर साल जनवरी में आयोजित विश्व आर्थिक मंच ऐसी ही संरचनाएं हैं। अधिक परंपरागत ढंग से देखें तो केवल तीसरे इंटरनेशनल को ही कुछ अहमियत वाली भूमंडलीय पार्टी माना जा सकता है।

यह स्वाभाविक ही होगा कि नयी वैश्विक पार्टियों या महत्वपूर्ण इंटरनेशनलों का उदय हो। क्या ये वर्तमान में प्रचलित नवउदारवादी उपभोक्तावादी मॉडल का विकल्प प्रस्तुत करेंगी या इन्हीं की विचारधारा और संरचना को मजबूत करेंगी यह देखना अभी बाकी है। क्या वामपंथी-पर्यावरणवादी मूल्यों से विकल्प उभड़ेंगे या धार्मिक संस्थाएं अथवा राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां और भी मजबूत बनेंगी?

अकादमिक दृष्टि से हम शोध के एक नए विषय को उभड़ता देख रहे हैं। साथ ही हम संभावित नयी वैश्विक पार्टियों के संदर्भ में राजनीतिक विचारों की व्यवस्था संबंधी कुछ प्रश्नों को भी रेखांकित कर रहे हैं। जैसे कि हाइकी पाटोमाकी तथा ताइवो ताइवेनेन (2006:44) कहते हैं—“विचारों की विभिन्नता को स्थायी मानते हुए, अनेक विश्व-दृष्टियों को होना होगा जो एक दूसरे से संबद्ध होते हुए भी अलग-अलग होंगी, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी तुलनात्मक रूप से संकीर्ण विचारों से संघर्ष करेंगी (और उनकी सांस्कृतिक संमृद्धि से बहुत कुछ सीखेंगी)।” दूसरा सवाल इन वैश्विक राजनीतिक पार्टियों के संगठनात्मक ढाँचे से संबंधित है। उदाहरण के लिए नेटवर्क के नए संगठनात्मक स्वरूप और संभावित वैश्विक राजनीतिक पार्टी संरचनाओं के साथ उनके संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तीसरा सवाल वैश्विक संस्थागत व्यवस्था से संबंधित है। भविष्य में किस प्रकार की व्यवस्था मौजूद होगी और इनका उदय कैसे होगा? आने वाले वर्षों में लोकतांत्रिक वैश्विक पार्टियों पर बहस निश्चय ही और भी गहरी होगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों पर होने वाली बहस में इसका योगदान होगा।

References

Amin, Samir (2006): "Towards the Fifth International?" in Sehm Patomäki, Katarina and Marko Ulvila (eds): *Democratic Politics Globally – Elements for a Dialogue on Global Political Party Formations*, NIGD Working Paper 1/2006

Gallup International (2005): Voice of the People 2005, Trends in Democracy, Global Summary, also available on-line at http://www.voice-of-the-people.net/ContentFiles/files/VoP2005/VOP2005_Democracy%20FINAL.pdf

Gill, Stephen (2006): "Reflections on Global Political Parties", in Sehm Patomäki, Katarina and Marko Ulvila (eds): *Democratic Politics Globally – Elements for a Dialogue on Global Political Party Formations*, NIGD Working Paper 1/2006.

Harvey, David (2005): *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford

Monbiot, George (2003): *The Age of Consent, A Manifesto for a New World Order*, Flamingo Press, London

Patomäki, Heikki and Teivo Teivainen (2006): "Global Political parties: toward a research programme", in Sehm Patomäki, Katarina and Marko Ulvila (eds): *Democratic Politics Globally – Elements for a Dialogue on Global Political Party Formations*, NIGD Working Paper 1/2006

Pratap, Vijay (2006): "Remarks for the discussion on global political parties", in Sehm Patomäki, Katarina and Marko Ulvila (eds): *Democratic Politics Globally – Elements for a Dialogue on Global Political Party Formations*, NIGD Working Paper 1/2006

Wallgren, Thomas (2006): "Party Systems, democracy and globalization", in Sehm Patomäki, Katarina and Marko Ulvila (eds): *Democratic Politics Globally – Elements for a Dialogue on Global Political Party Formations*, NIGD Working Paper 1/2006

लेखक परिचय

कैटरीना सेम पाटोमाकी की रुचि मुख्य रूप से भूमंडलीकरण और लोकतंत्रीकरण संबंधी विषयों से है। कैटरीना एन आई जी डी के साथ शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं। संस्थापक सदस्य, भूतपूर्व अध्यक्ष (1999) तथा वर्तमान कार्यकारी सचिव की हैसियत से इन्होंने कई प्रोजेक्टों का नेतृत्व किया है और *एन आई जी डी* के एजेंडा निर्धारण में योगदान किया है। *एन आई जी डी* से जुड़ने के पहले कैटरीना सेह पाटोमाकी ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे *काउंसिल ऑफ यूरोप, ओ एस सी ई*, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में अनेक हैसियतों में काम किया था। अभी वह कर्जों के सुलह समझौते की व्यवस्था पर शोधरत हैं। यह हेलसिंकी विश्वविद्यालय में उनके पी एच डी थीसिस का भी केंद्रीय बिंदु है।

मार्को उल्विला स्वतंत्र शोधकर्ता है तथा लोकतंत्र कार्यकर्ता हैं। वह टैम्पीर, फिनलैंड में स्थित हैं। उनका *कोएलिशन फॉर इनवाइरनमेंट एंड डेवलपमेंट* तथा *फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, फिनलैंड* जैसी संस्थाओं के साथ लंबे समय तक संबंध रहा है। उन्होंने समाजशास्त्र में टैम्पीर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। भारत में वह *वसुधैव कुटुंबकम्, सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज* तथा *लोकायन* से संबद्ध रहे हैं। हाल में वह फिनलैंड की ग्रीनपार्टी से भी संबद्ध रहे हैं जिसके अंतर्गत वह थोड़े समय के लिए विकास सहयोग मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आजकल वह *डेमोक्रेसी फोरम वसुधैव कुटुंबकम् –फिनलैंड* के सदस्य सचिव हैं तथा *एन आई जी डी* के अध्यक्ष भी हैं।

परिशिष्ट

कुछ लेखों के चुनिंदा अंश

क्षेत्रीय पार्टियां

देश-आधारित संगठनों से दूर हटना भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वृहत्तर भूमंडलीय लोकतंत्र की दिशा में एक कदम है। वर्तमान इतिहास में भूमंडलीकरण के साथ ही क्षेत्रीकरण भी एक महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति है।

अब तक क्षेत्रीय शासन से संबंधित दो प्रोजेक्टों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से चुने गए संसदीय निकायों की रचना हुई है। 1979 से ही यूरोपीय संघ के संसद के लिए सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता रहा है। मध्य अमेरिकी साझा बाजार के छः सदस्य देशों के मतदाता मध्य अमेरिकी संसद के लिए 132 प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसकी स्थापना ग्वाटेमाला सिटी में 1991 में हुई थी।

प्रत्यक्ष रूप से चुने गए क्षेत्रीय संसदों के उदय ने क्षेत्रीय स्तर पर *यूरोपियन पीपुल्स पार्टी*, *पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स* या *यूरोपियन फ्री एलांस* जैसी पार्टियों के गठन को बढ़ावा दिया है। मध्य अमेरिका में कोई विशिष्ट क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, हालाँकि सांसदों ने तीन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक की रचना की है।

इसी बीच कई क्षेत्रीय शासकीय ढाँचों में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए निकाय शामिल हुए हैं जिनमें सदस्य देशों की राष्ट्रीय विधायिका से सदस्यों की नियुक्ति की जाती है *पार्लियामेंट्री एसेंब्ली ऑफ दी काउंसिल ऑफ यूरोप* (उद्घाटन 1949 में), *द एंडियन पार्लियामेंट ऑफ दि एंडियन कम्युनिटी* (1979) तथा *पैन - अफ्रीकन पार्लियामेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन* (2004) इसके कुछ उदाहरण हैं।

न तो वर्तमान क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का, न ही क्षेत्रीय संसदों का भूमंडलीकरण पर कोई लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने समय समय पर वैश्विक मुद्दों को जनता की नजर में लाया है। अंतर्राष्ट्रीय पार्टी 'नेटवर्क' के सचिवालयों की तरह क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के ब्यूरो के पास बहुत ही कम साधन उपलब्ध थे। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियों तथा पार्टी व्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक राजनीति के लोकतंत्रीकरण के तर्क में एक अंतर्निहित दम तो है लेकिन इसका कुछ खास परिणाम अबतक सामने नहीं आया है।

साभार : स्कोल्ट, जैन आर्ट 2006:73-74

तृतीय इंटरनेशनल- एक भूमंडलीय पार्टी ?

गृह युद्ध, उपनिवेशवादी शक्तियों के हमले, नवजात सोवियत राज्य के गहन आर्थिक संकट के बीच ही मॉस्को में 1919 में *तृतीय इंटरनेशनल* की स्थापना हुई। यह पूरी तरह बोल्शेविक पार्टी और इसके क्रांतिकारी समाजवादी कार्यक्रम पर आधारित था। इसके अधिकांश प्रतिनिधि या तो बोल्शेविक थे या रूस में फंसे निर्वासित लोग। दुनिया में महज मुट्टीभर सही अर्थों में क्रांतिकारी पार्टियां थी और जनाधार रखने वाली तो और भी कम।

बोल्शेविक हमेशा से सच्चे अर्थों में एक और क्रांतिकारी इंटरनेशनल के पक्षधर थे। 1914 तथा सफल क्रांति के बाद, नए इंटरनेशनल की स्थापना की जाने वाली थी। लेकिन जिस कालावधि में यह पैदा हुआ उसके कारण इसकी प्रवृत्ति रूसी क्रांति तथा यूरोप में क्रांति की संभावनाओं की जरूरतों से निर्धारित हुई। लेनिन और बोल्शेविकों ने *तृतीय इंटरनेशनल* की स्थापना का उपयोग एक फौरी मकसद से किया?— क्रांति के प्रसार के द्वारा इसकी रक्षा।

क्रांतिकारियों के बीच बोल्शेविकों की अपार साख थी। अन्य पार्टियों की तुलना में उनके साधन, शक्ति, राजनीतिक सूझबूझ तथा कार्य बहुत अधिक थे। किसी अन्य पार्टी के पास दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से तपे हुए क्रांतिकारी नेताओं की ऐसी टीम नहीं थी जो बोल्शेविकों के पास थी। इस प्रकार, *कॉमिन्टर्न* शुरू से ही एकपक्षीय था।

क्रांतिकारी लहर थम गई, कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई और सोवियत संघ अलग-अलग पड़ा रहा। सोवियत संघ की कम्युनिष्ट पार्टी के अधःपतन के साथ ही *कॉमिन्टर्न* का अधःपतन भी चालू हुआ। यह मॉस्को द्वारा नियंत्रित एक साधन बन गया। इसका उद्देश्य मॉस्को की विदेशनीति को बढ़ावा देना बन गया न कि अन्य स्थानों पर क्रांति को सहयोग देना। *कॉमिन्टर्न* क्रांति की धारा को अवरुद्ध करने वाला, नयी पहलों को निष्प्राण करने वाला बन गया जिसके कारण स्वतंत्र मार्क्सवादी पार्टियों का विकास रुक गया। अंततः यह क्रांति के लिए आस्तीन का साँप बन गया।

1943 में *कॉमिन्टर्न* का औपचारिक विघटन साम्राज्यवाद को दी जाने वाली एक रियायत थी, अपने युद्धकालीन सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। लेकिन तबतक यह मृतप्राय हो चुका था। इसका रूप इंटरनेशनल का था लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं था।

साभार : पर्सी, जॉन, 2006:57

राजनैतिक "पार्टी" की बदलती अवधारणा

यदि हमें "वैश्विक पार्टियों" के विचार पर सोचना ही हो तो इसकी एक आलोचनात्मक समझ के लिए भी हमें "वैश्विक" और "पार्टियां" इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला कर देखना चाहिए और साथ ही दोनों शब्दों पर अलग-अलग करके भी विचार करना चाहिए। क्या वैश्विक पार्टियों के बारे में सोचने की बजाय, पार्टी व्यवस्था की वैश्विक संदर्भ में चर्चा करना अधिक अर्थवान नहीं होगा ? राजनीतिक पार्टियों के साथ लोग किस तरह का संबंध बनाते हैं, कैसे जुड़ते हैं ? हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि लोग वोट क्यों देते हैं या वोट से अलग क्यों रहते हैं। हमें

इस पर भी बात करनी चाहिए कि लोगों की समझ में एक स्वस्थ पार्टी व्यवस्था किसे कहते हैं तथा लोग पार्टी में क्यों शामिल नहीं हैं ? कुछ मुद्दे हैं जो वैधता के सवाल से जुड़ते हैं— मसलन लोगों की समझ में एक न्याय संगत व्यवस्था क्या है ? या कि पार्टी व्यवस्था के बारे में उनकी क्या मान्यता है। यदि हम 'पार्टी' शब्द का अर्थ वयस्क मताधिकार और बहु-पार्टी व्यवस्था वाले देशों तक भी सीमित रखते हैं तब भी आज से 30 या 50 साल पहले पार्टी की जो अवधारणा थी उसमें और आज पार्टी व्यवस्था की समझ में बिल्कुल नाटकीय ढंग से बदलाव आया है।

(सौजन्य : प्रताप, विजय, 2006-173)

पार्टी इंटरनेशनल तथा वैश्विक सार्वजनिक नीतिगत मुद्दे

विभिन्न पार्टी इंटरनेशनलों में वैश्विक सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर *सोशलिस्ट इंटरनेशनल* ने विकासशील देशों की कर्ज संबंधी समस्याओं, आग्रजन, ब्रेटनवुड संस्थाओं पर बातचीत, क्योटो- समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे मुद्दों पर समितियों, कार्यकारी समूहों तथा अभियानों का समर्थन किया है। *चौथे इंटरनेशनल* ने वर्तमान पूंजीवाद तथा कामगारों के मुद्दों को विशिष्ट रूप से भूमंडलीय मुद्दों के रूप में देखा है। 'लिबरल इंटरनेशनल' ने हमेशा 'भूमंडलीकरण की चुनौतियों' पर विचार किया है।

फिर भी देश – आधारित पार्टियों बीच इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा- चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। दशकों की अपनी गतिविधियों के बावजूद, इन अंतर्राष्ट्रीय पार्टी संस्थाओं का वैश्विक राजनीति पर बहुत हल्का असर पड़ा है। इन नेटवर्कों में राजनीतिक पार्टियों के कुछ गिने-चुने सदस्यों, नेताओं तथा सहयोगियों ने ही सार्थक समय और साधन लगाया है।

इन साधनों से भूमंडलीकरण में किसी भी प्रकार के उल्लेखनीय लोकतंत्रीकरण के लिए देश-आधारित पार्टियों के बीच और भी व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जरूरत है। वैश्वीकरण और इसकी शासन संबंधी चेतना को बढ़ाने, राज्यतर तथा निजी नियामक संस्थाओं को इसमें शामिल करने, वैश्विक विषमता से लड़ने, भूक्षेत्रतर तथा भूक्षेत्र आधारित जनता को मंच प्रदान करने के लिए पार्टी इंटरनेशनलों को और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। सिद्धांततः परंपरागत राजनीतिक पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग की बड़ी संभावना मौजूद है लेकिन व्यावहारिक रूप में अबतक इसके परिणाम नगण्य रहे हैं।

साभार : स्कोट, जैन आर्ट, 2006:72-73

भूमंडलीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में पाँच अवधारणाएं

1. वैश्विक राजनीतिक पार्टियों के अध्ययन के लिए दीर्घकालीन दृष्टि की जरूरत है, जिसकी जड़, जैसा कि फर्नान्ड ब्राउडेल ने कहा है, इतिहास की गहरी खाई में है।
2. अगर राजनीतिक पार्टियाँ तात्कालिक और दीर्घकालीन राजनीतिक सवालों के साथ लगातार जूझती नहीं हैं और अपनी प्रासंगिकता नहीं बनाए रखती हैं तो उन्हें पुराना पड़ जाने से कोई बचा नहीं सकता।
3. हमें इस मान्यता के धोखे से बचना चाहिए कि प्रतिरोध की सभी शक्तियाँ या प्रगतिशील ताकतों को एजेंसी के किसी एक स्वरूप जिसे हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं, में एकीकृत किया जा सकता है या किया जाना चाहिए।
4. हमें राजनीतिक एजेंसी को संगठन की बजाए आंदोलन के रूप में परिकल्पित करना चाहिए।
5. सफल राजनीतिक आंदोलनों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने स्वरूप को संभव स्वप्नजगत (युटोपिया) तथा लामबंद कर सकने लायक मिथकों से जोड़ें।

साभार : गिल, स्टीफन 2006 :147-9

लोकतांत्रिक वैश्विक राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्तें

अगर हम इस मूल समझ से सहमत हैं कि पार्टियाँ एक प्रकार के स्वैच्छिक संघ हैं जो राज्यसत्ता के प्रयोग के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वैश्विक पार्टियों के बारे में हम दो सीख ले सकते हैं।

पहला कि ऐसे संघ जो पक्के अर्थों में वैश्विक पार्टियाँ हैं तभी संभव है जबकि इस प्रकार के संगठन मौजूद हों जो दुनिया भर के पैमाने पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस परिस्थिति में उसी हद तक वैश्विक पार्टियों का अस्तित्व होता है जिस हद तक सिद्धांततः दुनियाँ के हर हिस्से के लोगों के लिए स्वैच्छिक नागरिक संघ पहुंच के भीतर होते हैं जो उन संगठनों पर शासन के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज वैश्विक रूप से शक्तिशाली ऐसे अनेक संगठन तो हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कई सभी लोगों की पहुंच के अंदर रहने वाले संघों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किए जा सकते। इस नकारात्मक सूची के सबसे बड़े उदाहरण अमेरिका और बड़े कॉरपोरेशन हैं। इसके सकारात्मक उदाहरणों में संयुक्त राष्ट्र संघ को गिना जा सकता है।

दूसरी सीख यह है कि लोकतंत्र के औजार के रूप में वैश्विक पार्टियों की सफलता की शर्तें बहुत ही कठोर हैं। इनमें से सर्वप्रमुख है— (1) राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा वैश्विक रूप से सुगम, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के द्वारा ही तय हो और आदर्श रूप में पहल तथा जनमत संग्रह का अधिकार भी लोगों को उपलब्ध हो। (2) ऊपर सुझाई गयी छवि के अनुरूप ही एक न्यूनतम 'लोकतांत्रिक जीवन' होना चाहिए ताकि वोट गिराना एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आचरण बन सके।

पार्टियों की 'कठोर' परिभाषा लेते हुए, जो कोई भी व्यक्ति वैश्विक पार्टियों को बढ़ावा देना चाहता है उसे इन सभी शर्तों का उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से पालन करना चाहिए। भूमंडलीय शक्तियों पर लोकतांत्रिक कायदों को लागू करने की फौरी जरूरतों को चुनावों की निष्पक्षता तथा चुनावों को अर्थ देने वाले लोकतांत्रिक जीवन की गुणवत्ता संबंधी वास्तविक जरूरतों से संतुलित किया जाना भी आवश्यक है।

साभार: वालग्रेन, थॉमस 2006:158-9

21 वीं सदी में राजनीतिक होने का क्या अर्थ है ?

काफी समय से यह बात साफ हो चुकी है कि विश्व राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है। भूमंडलीकृत होती जा रही दुनिया में आने वाले नए किरदारों ने राजनीति के अर्थ को और भी व्यापक बना दिया है। वैश्विक कॉरपोरेशन, गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क तथा अंतर्देशीय सामाजिक आंदोलन इसके कुछ उदाहरण हैं जिनकी प्रायः चर्चा की जाती है।

हालांकि उनके नएपन को बढ़ाचढ़ कर पेश किया जाता है और उनकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों तथा उदाहरणों को दरकिनार किया जाता है, उनके शामिल होने से वैश्विक मामलों पर होने वाली बहस और भी समृद्ध होती है।

इन प्रत्यक्षतः नए पात्रों के प्रादुर्भाव को अकादमिक जगत तथा ज्ञानोत्पादन के अन्य मंचों पर स्वीकार तो किया जाता है लेकिन राजनीति को पुनर्परिभाषित करने की दृष्टि से इस प्रक्रिया की पूरी तरह से पड़ताल नहीं की गयी है। भूमंडलीकृत 21 वीं सदी में राजनीतिक होने का क्या अर्थ है? आदर्श रूप में, नागरिकों का कौन सा समूह लोकतांत्रिक परिवर्तन का एजेंट बन सकता है या बनना चाहिए? हम इस बात को संभावित और वांछित मानते हैं कि ये सवाल आने वाले वर्षों में राजनैतिक और अकादमिक बहसों में और भी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं।

उभड़ते हुए वैश्विक नागरिक समाज में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका की व्याख्या यदाकदा ही की जाती है। पार्टियों को नागरिक समाज से अलग समझा जाता है— जैसा कि पुराने समय में किया जाता था। जबकि अनेक राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियों के स्तर को बदलकर खुद को अंतर्देशीय बना चुकी हैं, प्रायः यही माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां भूक्षेत्रीय राज्य की सीमाओं के अंदर ही रहती हैं।

साभार: पाटोमाकी, हाइकी तथा ताइवो ताइवेनन 2006:25

अंतर्देशीय लोकतांत्रिक आंदोलनों का उदय

प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने की हाल की कोशिश का उद्देश्य वैश्विक शासन तथा अर्थव्यवस्था पर लोकतांत्रिक प्रभाव छोड़ना है। एक अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की दिशा में कारगर प्रयत्नों को संगठित करने के दौरान कार्यकर्ता पहले की गलतियों से बचना चाहते हैं। पिछले चार सदियों में अंतर्देशीय सामाजिक आंदोलनों के निष्कर्षों, विश्व-क्रांतियों तथा वैश्विक शासन के विकास को ध्यान में रखते हुए इस नए प्रोजेक्ट को विश्व ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की जरूरत है। वैश्विक शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने की मांग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन उभड़ रहा है।

साभार: चेज जुन तथा एलेन रीस 2006: 82,93

नागरिक समाज का गैर-राजनीतिकृत पक्ष

ऐसे कई लोग हैं जो विश्व सामाजिक मंच को स्थाई रूप से अधिकतम नपुंसकता की स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं। जिस विचारधारा के आधार पर वह इसकी निष्क्रियता को सही साबित करना चाहते हैं, वह सुविख्यात है। उनकी एक मान्यता इस मंच और स्वयंभू 'बहुल-वामपंथ' (खासकर यूरोप में) की बहुलता के बीच साम्य पर आधारित है। उनकी दूसरी मान्यता "अराजनीतिक नागरिक समाज" (या यहाँ तक कि राजनीति विरोधी नागरिक समाज) है।

उनका मकसद है कि विश्व सामाजिक मंच को दावोस मंच के एक पूरक के रूप में बदल दिया जाए। दूसरे शब्दों में उदारवाद, पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करने की बजाय वो न्यूनतम 'सामाजिक मांगों' (जैसे गरीबी के खिलाफ संघर्ष) के नाम पर इन सिद्धांतों को नयी वैधता प्रदान कर रहे हैं। तथाकथित 'नागरिक समाज' के ये संघ (यथासंभव गैर- राजनीतिक) इन मांगों को स्वरूप प्रदान करने के खास साधन माने जाते हैं।

साभार :अमीन, समीर 2006:142

